Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.04, No.07, July,2025

नई शिक्षा नीति 2020: समस्याएँ और समाधान

*आंशिक शुक्ला
शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र)
महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली

****

शोधसार: *नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं। भारत में शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला भी है। नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो 34 वर्षों बाद शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य एक समावेशी, लचीली, बहुआयामी और कौशल-आधारित शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। हालाँकि, इस नीति के अनेक सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ और विवादास्पद बिंदु भी सामने आए हैं। इस शोध-पत्र में NEP 2020 की मूल विशेषताओं, प्रमुख समस्याओं तथा उनके संभावित समाधान का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।*

शब्दबिन्दु:- *नई शिक्षा नीति 2020, भारत की शिक्षा नीति में बदलाव, के. कस्तूरीरंगन समिति की भूमिका, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार, समावेशी और लचीली शिक्षा प्रणाली, कौशल-आधारित बहुआयामी शिक्षा, नीति के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, शिक्षा का सामाजिक व राष्ट्रीय विकास में योगदान, 1986 की नीति से तुलना, और NEP 2020 का विश्लेषण।*

****

नीति का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं, जिसमें उसका विनियमन और प्रशासन भी शामिल है, का पुनरीक्षण और पुनर्निर्माण करना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नया ढाँचा स्थापित करना है। उदाहरण के लिए, सतत विकास लक्ष्य 4 भारत की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के पोषण पर ज़ोर देती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे बुनियादी कौशल से लेकर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या-समाधान जैसे उन्नत कौशल और सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं तक, संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए।

- इस शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा की स्थापना की गई।
- 21वीं सदी के कौशलों से युक्त मानव संसाधन का निर्माण हुआ है और इस शिक्षा नीति से कभी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
- भारतीय संस्कृति, मूल्यों और वैश्विक मानकों के समन्वय द्वारा शिक्षा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- 5+3+3+4 पाठ्यक्रम की संरचना की गयी हैं।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया हैं।
- तीन भाषा सूत्र।मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया हैं।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रो की स्थापना की गई।
- स्कूल और उच्च शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया हैं।
- उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया हैं।
- शिक्षा का व्यावसायिकरण रोकने का प्रयास किया गया हैं।

नई शिक्षा नीति में निहित संभावनाएँ

- छात्र-छात्राओं के सीखने की प्रक्रिया में लचीलापन आयेगा ।
- पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा में समन्वय हो सके तथा दोनों साथ साथ कारगर हों।

- ❖ शिक्षा का स्थानीयकरण और वैश्वीकरण किया गया हैं।
- ❖ शिक्षकों की भूमिका में सुधार और मानकीकरण किया गया हैं।
- ❖ उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण को समर्थन दिया गया हैं।
- ❖ डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया हैं।
- ❖ राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना की गयी हैं।

नई शिक्षा नीति की प्रमुख समस्याएँ

क्रियान्वयन की चुनौती

- नीति के कई पहलू राज्य सरकारों के अधीन हैं, लेकिन नीति का स्वरूप केंद्र-प्रधान है।
- शिक्षकों और विद्यालयों को प्रशिक्षित करने की व्यापक आवश्यकता है।

भाषा नीति से संबंधित विवाद

मातृभाषा में शिक्षा की बाध्यता से व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी को प्रमुखता देने के आरोप से क्षेत्रीय असंतुलन बना हैं। तथा इस शिक्षा नीति में तीन भाषाओं को प्रमुख माना गया हैं।

डिजिटल डिवाइड की समस्या

इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों अभी भी डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण नई शिक्षा नीति पूर्णरुप से कारगर नहीं हैं, इंटरनेट की सीमित उपलब्धता होने के कारण भी आनलाइन शिक्षा का महत्व कम बना हैं। ई-लर्निंग में तकनीकी और भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा हैं।

वित्तीय संसाधनों की कमी

शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की कमी एक जटिल समस्या है, लेकिन इसे प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हल किया जा सकता है। सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, GDP का 6% शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन वास्तविक व्यय अभी भी 4% के आस-पास है, नए संस्थानों की स्थापना और संसाधनों की जरूरत के लिए बजट अपर्याप्त है।

शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता

ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी के कारण भी नई शिक्षा नीति पूर्णरुप से कारगर नही हो पा रही हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता संदेह के घेरे में हैं और योग्य शिक्षक की कमी के कारण इस शिक्षा नीति में कमियां दिखाई दे रही हैं।

उच्च शिक्षा में संस्थागत संरचना की जटिलता

HECI जैसे नए संस्थानों की स्थापना में स्पष्टता का अभी भी अभाव है।

स्वायत्तता बनाम जवाबदेही का संतुलन कठिन।

संभावित समाधान और सुझाव

क्रियान्वयन के लिए समन्वय प्रणाली

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन।

जिला स्तरीय शिक्षा योजना और निगरानी समितियों की स्थापना।

भाषा नीति में लचीलापन

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन, परंतु बाध्यता नही।

अंग्रेजी और अन्य वैश्विक भाषाओं को विकल्प के रूप में जारी रखना।

डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे का विकास

- ❖ सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास, इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ना।
- ❖ कम लागत वाले टैबलेट, मोबाइल और डिवाइस उपलब्ध कराना।
- ❖ शिक्षकों और छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देना।

वित्तीय निवेश में वृद्धि

शिक्षा के लिए GDP का न्यूनतम 6% व्यय अनिवार्य करना।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से संसाधनों का विकास।

CSR के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र को समर्थन।

शिक्षकों के प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी।

निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) कार्यक्रम।

ICT आधारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

नवाचार और शोध को बढ़ावा

विश्वविद्यालयों में रिसर्च को अनिवार्य बनाया जाए।

बहुविषयक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना।

छात्रों में नवाचार संस्कृति को विकसित किया जाए।

वैश्विक संदर्भ में NEP 2020 का विश्लेषण

अन्य देशों की नीतियों से तुलना

फिनलैंड: व्यक्तिगत शिक्षा पर ज़ोर, शिक्षकों को सर्वोच्च दर्जा।

दक्षिण कोरिया: टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षा।

अमेरिका: शिक्षा में स्थानीय स्वतंत्रता और नवाचार।

NEP 2020 में इन वैश्विक उदाहरणों से प्रेरणा मिलती है, परंतु भारतीय विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे साकार करना चुनौतीपूर्ण है।

सामाजिक प्रभाव

- ❖ महिलाओं की शिक्षा में बढ़ावा
- ❖ वंचित वर्गों की शिक्षा तक पहुँच
- ❖ आदिवासी, ग्रामीण और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष उपाय
- ❖ व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी में कमी

आलोचना और चिंता के बिंदु

- बहुभाषीयता की जटिलता
- स्कूल छोड़ने वालों की बढ़ती संख्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं
- रोजगार और शिक्षा के बीच तालमेल की कमी

- शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच अंतर को दूर करने के लिए ठोस योजना का अभाव

निष्कर्ष (Conclusion)

नई शिक्षा नीति 2020 एक दृष्टिकोण परिवर्तनकारी दस्तावेज है, जो भारत को वैश्विक शिक्षा मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता रखता है। यह न केवल छात्रों के कौशल और सृजनात्मकता को विकसित करने का प्रयास करती है, बल्कि एक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में भी प्रयासरत है। हालाँकि, यह तभी सफल हो सकती है जब इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक दृष्टिकोण, राज्यों की सहभागिता, वित्तीय सहायता, और प्रशिक्षित मानव संसाधन को शामिल किया जाए।

संदर्भ (References)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार।

2. UGC Guidelines on NEP 2020.

3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट्स।

4. NITI Aayog शिक्षा सुधार रिपोर्ट।

5. UNESCO Global Education Monitoring Report.

6. विभिन्न समाचार पत्र व शिक्षाशास्त्र पत्रिकाएँ।

*Corresponding Author: Anshik Shukla

E-mail:
Received: 02 June,2025; Accepted: 27July 2025. Available online: 30 July, 2025
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License